

मन होवे निर्भीक जहाँ पर,
रहे सदा ही ऊँचा शीश;

जहाँ ज्ञान हो मुक्त मलय-सा;

जहाँ विश्व विछिन्न नहीं हो सकुचाई गृह
दीवारों से,

खंड-खंड मेरे जगदीश।

जहाँ शब्द जन्मा करते हैं
सत्य, स्वच्छ गहराई से;

होवे वहाँ प्रयत्न निरंतर
हर कौशल हित बाँह पसारे;

जहाँ लक्ष्य का निर्मल निर्झर
बुझे दिलों की मरुस्थली में
लुप्त नहीं हो, लुप्त नहीं हो।

और जहाँ मन तुझसे प्रेरित
मुक्त विचारों और कर्मों में,
बढ़ता जाए-बढ़ता जाए।

स्वतंत्रता के उसी स्वर्ग में,
हे प्रभु, मेरा देश दुलारा
आँखें खोले-आँखें खोले।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

© राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जनवरी 2007

प्रकाशन

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग

भारत सरकार

धर्म मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-21

www.knowledgecommission.gov.in

हिन्दी रूपांतरण

अखिल मित्तल

रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविता का हिंदी भावानुवाद

डा.शेरजंग गर्ग

डिजाइन एवं मुद्रण

न्यू कान्सेप्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स, प्रा. लि. नई दिल्ली-76

www.newconceptinfo.com

प्रस्तावना

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जब अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्र के सामने प्रस्तुत कर रहा है तो हम यह देखकर बहुत उत्साहित हैं कि भारत में दुनिया का एक प्रमुख ज्ञानवान समाज बनकर उभरने की कितनी अपार संभावनाएँ हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस आयोग की स्थापना यह सोचकर की थी कि देश के विशाल ज्ञान भंडार का उपयोग करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाए ताकि देश के लोग 21वीं सदी की चुनौतियों का पूरे विश्वास के साथ सामना कर सकें। हम समझते हैं कि यह काम कितना कठिन है। इसके लिए न सिर्फ साधनों और समय की जरूरत है, बल्कि दूर-दृष्टि और सही समझ भी आवश्यक है। हमें खुशी है कि हमने इस दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्यक्षेत्र में आने वाले पाँच प्रमुख विषय, ज्ञान की सुलभता, सिद्धांतों, रचना, उपयोग और सेवाओं से जुड़े हुए हैं। हमने इन्हीं संदर्भों को ध्यान में रखते हुए ज्ञानवान समाज की रचना करने के तरीकों पर विचार किया है और उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान ज्ञान की सुलभता बढ़ाने पर दिया है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 2006 में जिन दस विषयों पर सिफारिशें दी हैं, उनमें से छह का सीधा संबंध सुलभता से है। हमने यह काम सबको समाहित रखने वाले समाज की रचना के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दर्शन के अनुरूप किया है। उभरता हुआ ज्ञानवान समाज और उससे जुड़े अवसर हमारी अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज के लिए नई आवश्यकताएँ और नई चुनौतियाँ पेश कर रहे हैं। भविष्य की हमारी संपन्नता हमारी नीतियों, कार्यक्रमों और लोगों पर निर्भर है, जो ज्ञान की तलाश में ज्ञान का लगातार सृजन करते हुए उसका उपयोग भी कर सकें।

हमने बहुत सारे विषयों पर विचार किया है। इनमें उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार, सार्वजनिक पुस्तकालय व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव, ज्ञान नेटवर्क की रचना राष्ट्रीय पोर्टलों की स्थापना व्यावसायिक शिक्षा का रूप बदलना, सरकारी प्रक्रियाओं में फेरबदल और ई-प्रशासन को नागरिकों के अनुकूल बनाने जैसे विषय शामिल हैं। हमारी सिफारिशों के प्रभाव अगले दशक में और उसके बाद महसूस होंगे। हमने पूरी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक, पारदर्शी और सहभागी रखने पर विशेष ध्यान दिया है। इसके लिए हमने सरकार, संसद, राजनीति, शिक्षा, उद्योग, समाज और मीडिया से जुड़े तमाम विशेषज्ञों और जानकारों के साथ व्यापक चर्चा की है। हमारी सिफारिशों में संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों और लोगों के सरोकार और आकाँक्षाएँ झलकती हैं और उन्हें इनमें पूरा स्थान भी दिया गया है।

आयोग के सदस्यों ने हमारी सिफारिशों के हर पहलू पर बहुत मेहनत से काम किया है। मैं सभी सदस्यों का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने अपने काम को इतनी अधिक निष्ठा के साथ पूरा किया है, हालाँकि वे सब जानते हैं कि उनकी मेहनत का फल बहुत दूर जाकर मिलेगा। अनेक मुद्दों पर हमारे बीच सहमतियाँ और असहमतियाँ रही हैं, किन्तु उन्हें हमेशा लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप व्यक्त किया गया है। मैं विभिन्न कार्यदलों के सदस्यों और सचिवालय के सदस्यों को भी उनके योगदान और सहायता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं प्रधानमंत्री कार्यालय और योजना आयोग के समर्थन और मार्गदर्शन के लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

हमें आशा है कि हमने अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में जो काम किया है, वह सरकार के लिए मूल्यवान साबित होगा और प्रशासन उसे पूरे उत्साह तथा समर्थन के साथ अपनाएगा। हमें यह भी आशा है कि हमारी सिफारिशों पर अपेक्षित ध्यान दिया जाएगा, लोगों के बीच उनके बारे में खुलकर चर्चा, बहस और संवाद होगा, जिससे जनमत को एकजुट करने और उसे आकार देने में मदद मिलेगी। हम यह बात 25 वर्ष से कम आयु के उन 55 करोड़ लोगों को ध्यान में रखकर कह रहे हैं, जिन्हें ज्ञान के इन नए प्रयासों से सबसे अधिक लाभ मिलेगा। भारत का भाग्य अब उनके हाथों में है। यह सिफारिशें करते समय हमने सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का रखा है कि ज्ञान लोगों, भारत के आम लोगों के जीवन को किस तरह प्रभावित करेगा। हम समझते हैं कि ज्ञान का मतलब जागरूक लोकतंत्र में सु-शासन से किसानों को जल साधनों, भूमि की किस्म और उर्वरकों के बारे में सही और सटीक सूचना सुलभ कराना है, विद्यार्थियों को स्कूलों और कॉलेजों में उत्तम किस्म की उपयोगी शिक्षा और अच्छी नौकरियाँ सुलभ कराना है, वैज्ञानिकों को सभी साधनों से सज्जित आधुनिक पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं की सुविधा सुलभ कराना है, उद्योगों को दक्ष श्रम शक्ति सुलभ कराना है और लोगों को सशक्तता का बोध दिलाना है।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें वास्तव में तत्काल कार्रवाई शुरू करने का आह्वान करती हैं। हमें अभी तुरंत इस दिशा में सन्नद्ध होना होगा।

सैम पित्रोदा
अध्यक्ष, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग

विचारार्थ विषय

- शिक्षा व्यवस्था में उत्कृष्टता लाना ताकि वह 21वीं शताब्दी में ज्ञान की चुनौतियों का सामना कर सके और ज्ञान के क्षेत्रों में भारत के स्पर्द्धात्मक लाभ में वृद्धि कर सके।
- विज्ञान और टेक्नॉलॉजी प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना।
- बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़े संस्थानों का प्रबंधन सुधारना।
- खेती और उद्योग में ज्ञान के उपयोग को बढ़ावा देना।
- सरकार को नागरिकों के लिए एक असरदार, पारदर्शी और जवाबदेह सेवा प्रदान करने वाली संस्था का रूप देने में ज्ञान क्षमताओं के उपयोग को बढ़ावा देना और लोगों को अधिक-से-अधिक लाभ पहुँचाने के लिए ज्ञान के व्यापक प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के लिए तीन वर्ष की समय सीमा निर्धारित है:

2 अक्टूबर, 2005 से 2 अक्टूबर 2008

इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रमुख प्रयासों को उजागर करने के साथ-साथ आयोग का संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है। इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना के प्रथम वर्ष में उसके प्रमुख प्रयासों और प्रधानमंत्री को भेजी गई सिफारिशों के साथ-साथ आयोग का संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है।

विषय सूची

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग	1
ज्ञान की सुलभता	7
ज्ञान के सिद्धांत	11
ज्ञान की रचना	15
ज्ञान का उपयोग	19
सेवाएँ प्रदान करने की व्यवस्था	21
सिफारिशें	25
परामर्श	67